Policy in terms of inducing the private sector was to wipe out the waiting list so far as telephones are concerned, particularly so far as the village telephones are concerned. Now, what is revealed from the existing waiting list is that the lag in terms of availability of village telephones is not even; it is uneven and it is concentrated in certain telecom circles. The results of the bidding also show that for those circles for which there is no bidding, for which no private company is coming forward or also for those circles where the waiting lists of village telephones are the highest, the basic contention that was made out in arguing for the National Telecom Policy, in my opinion, was not vailed. Therefore there is need for further augmenting the allocation for wiping out the waiting lists of village telephones from the DoT funds itself, and as we know, as distinct from some other Government Departments, DoT is a revenue earning Department. But here also, Mr. Chairman Sir, the answer that we got last year, in 1995, was that the DoT's target had fallen short. Is it a fact that there was a delay on the part of the DoT to actually order supply of equipments in a systematic manner so that the kind of target and the kind of efficiency that the DoT was actually having could not be maintained? ....*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please sum up and put your question.

SHRI NILOTPAL BASU: Is there any conscious Government attempt from within the DoT to sabotage its own programme?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: चेयरमैन सर, माननीय हमारे मित्र जी ने जो कहा है कुछ हद तक सही है। पिछले वक्त एक लाख पांच हजार का लक्ष्य था जिसमें 31,496 टेलीफोन ही लग पाए। इक्विपमेंट सप्लाई में देरी की वजह से ही ऐसा हुआ। जो इक्विपमेंट के सप्लाई के आर्डर्स दिए गए कुछ वे भी देर में दिए गए। लेकिन हमने इस वर्ष उसमें काफी परिवर्तन किया है। हमने सब बजटरी एलोकेशन भी अलग कर दिया है और श्रीमन् इस वर्ष जो जानकारी हमको दी गई है उसके अनुसार इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। इस वर्ष शत-प्रतिशत लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे और सुधार के लिए हमने पहले ही माननीय सदन के सामने निवेदन कर दिया कि हम इस पर स्वयं गंभीर हैं और कोशिश करेंगे कि ग्रामीण टेलीफोन सुविधा में सुधार हो।

श्री नीलोत्पल बसु: कोई प्रयास था कि सप्लायी में देर हो, आर्डर करने में क्या देर हुआ और कैसे देर हो गई?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: आर्डर में देरी हुई। कैसे हुई, यह पता नहीं, लेकिन आर्डर में देरी हुई।

श्री नीलोत्पल बसु: इसके बारे में कोई जांच आप करवायेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और यहजिम्मेदारी लगाने की कोशिश करेंगे या नहीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् इसको जरूर दखेंगे और अगर किसी की नीयत में कोई ऐसी बात हुई तो हम इसको देखेंगे, मगर वैसे ही कोई गड़बड़ होगी तो गलती नहीं है। लेकिन अगर गलत नीति से हो तो उसको हम अवश्य देखेंगे।

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1995-96 में बिहार में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सेवा को जोड़ने का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: यह जब कहीं पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो बिहार का भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और श्रीमन्, सब से ज्यादा अगर ग्रामीण टेलीफोन सुविधा की कमी है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ही है और इस वर्ष जो लक्ष्य रखा गया है वह इन तीन प्रांतों में, दूसरे अन्य प्रांतों के मुकाबले में ज्यादा है।

Plight of Indians in Gulf Countries

*202. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:
SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:†

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some Indian citizens are leading a very miserable life in various Gulf countries;

(b) whether Government have conducted any official level inquiry in this regard and the steps taken so far; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) The living conditions for Indian citizens in various gulf

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kanaksinh Mohansinh Mangrola.

countries are generally satisfactory. However, there have been a few instances wherein living and working conditions for Indian workers are unsatisfactory.

(b) and (c) The Government of India, through Indian Missions abroad, maintains regular contact with foreign Governments to ensure the welfare and to improve conditions of Indian workers in the respective countries. The Indian Missions at first try to resolve the differences between the aggrieved worker and the employer to arrive at a mutually acceptable solution. Wherever necessary, cases are taken up with the concerned authorities of the foreign Government to persuade the employers to redress the grievances of Indian workers. Where no alternative employment or any solution is possible despite best efforts of the Mission, all assistance is given to facilitate repatriation of the aggrieved worker.

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न सीधा-सादा था कि खाड़ी देशों में जो भारतीय वहां रहते हैं इनकी परिस्थिति क्या है, तो सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि परिस्थितियां संतोषजनक हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सऊदी अरब में जो अपने लोग वहां रहते है और खाड़ी देशों में कितने लोग जेल में हैं और खास करके मेरे को यह जानकारी है कि सऊदी अरब अपने भारत के दूतावास को कोई भी इन्फर्मेशन देता नहीं है कि जेल में कितने लोग हैं, कितने साल से हैं और इनकी परिस्थिति क्या है, तो सरकार इसके ऊपर प्रकाश डाले?

श्री रमाकांत डी० खलप: सभापति महोदय, सऊदी अरब में कुल मिलाकर अपने भारतवर्ष में 13 लाख भारतवासी यह काम करते हैं और इनमें से कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी दे रखी है। लेकिन इनका जो नंबर है वह बहुत कम है। 1992 में 1,963, 1993 में 2,730 और 1994 में 3,312 कंप्लेंट्स फाइल हुई। इनका रेशो अगर आप देखें तो वह बहुत कम है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: श्रीमन्, यह रेशो का सवाल नहीं है। हजार नागरिक आपके देश का तकलीफ में है, अमरीका तो एक आदमी के लिए भी झगड़ने के लिए तैयार होता है।

श्री रमाकांत डी० खलप: सर, माननीय सभासद को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: सर, प्रतिवर्ष यह संख्या बढ़ी है।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Leave it to the Law Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, human beings are not just statistics.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Let me inform the hon. Member that our missions abroad take. ...*(Interruptions)*... Let me inform the hon. Member that our missions abroad take cognisance of even the slightest complaints filed by our Members or citizens there. Even if it is a complaint by one person, we take into consideration that complaint. We inquire into it and we provide solace to Indian citizens abroad. Our missions are doing their work very satisfactorily.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: सर, सऊदी अरबिया ने पूरे मानवाधिकार को भारत के खिलाफ बिल्कुल इसको अपमानित किया है क्योंकि भारत के दूतावास को पूरी इसकी जानकारी है ही नहीं कि कितने भारतीय जेल में हैं। मेरे पास पूरी इन्फोरमेशन है इनकी। एक तो आप इसका जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, it is very important Question. It should be postponed.

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: दूसरा, मेरा प्रश्न यह था, माननीय सभापति जी, कि जो भारत से युवाधन विदेशों में ले जाया जा रहा है, इसके लिए अपने देश में, पूरे देश में कई बड़ी-बड़ी एजेन्सियां काम कर रही हैं, तो इनके खिलाफ, कितनी एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही की है? इसकी भी जानकारी कराएं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is a very important Question. Sir, even Members of Parliament also had some experience with our missions in Gulf countries. Let the External Affairs Minister come here. ...*(Interruptions)*... If the hon. Chairman feel . . . . I*nterruption*). The dead body of a worker, in spite of a telephonic call to the Indian mission there. ...*(Interruptions)*... Let the External Affairs Minister come here...

MR. CHAIRMAN: Then you raise a discussion on it. You raise a discussion on it. It is a specific question. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: It is general question.

MR. CHAIRMAN: If you want to discuss it with the Foreign Minister, please raise some sort of discussion or resolution of Calling Attention or whatever you want.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir,....

MR. CHAIRMAN: Let us go ahead with the Question Hour.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, millions of employees. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I would like to go ahead with this Question. Mr. Mangrola, I have asked you to put the second supplementary. What is this?

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: माननीय सभापति जी, मेरा यह सीधा-सादा प्रश्न है कि हिन्दुस्तान में से युवा धन को विदेश ले जाने के लिए अपने भारत में जो एजेन्सियां काम कर रही हैं, इसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? और, ऐसी कितनी एजेन्सी है, जिनके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही की है?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, let me inform the hon. Member that this question which he has put pertains to the Labour Ministry. Let us make a clear distinction. This question pertains to the Labour Ministry. It is true that there are organisations which have been sending our youth abroad. Some of these organisations are not doing their work properly. Some complaints are there. But these organisations may or may not be registered organisations. The complaints are taken care of by the Labour Ministry. The Labour Ministry is seized of such matters. If there are any complaints of cheating or illegal activities committed by them, there are agencies which have been taking care of those complaints. If you ask me about the action taken against such people, as and when we receive any complaints, those complaints are handed over to the concerned department of the Ministry.

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: सर, मेरा सीधा या सवाल है आपसे कियह जो विदेश में ले जा रहे हैं हमारे युवा धन को, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? इनको, युवा धन को फुसला कर, फंसा कर वहां ले जा रही हैं विदेशी कंपनियां। यह मैं आपको बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामाकांत डी. खलप: सर, हमारे युवा लोग देश के बाहर नौकरी के वास्ते जाते रहते हैं। वहां उन्हें पगार मिलती है। भारत में उनकी जो स्थिति है उससे अच्छी स्थिति पगार के बारे में, वहां पर उन्हें मिलती है। इसलिए भारत में से कई लोग, कई हमारे नौजवान, हमारे डिपार्टमेंट से वीसा लेकर, पासपोर्ट लेकर बाहर जाते हैं। बाहर जाने के लिए जो फेसिलिटी उन्हें देनी चाहिए वह फेसिलिटी हम उन्हें देते हैं। लेकिन, अगर आपका कहना है कि उनके जाने में कुछ ऑब्सट्रशन ले रखे हैं तो वह ऑब्सट्रशन हम नहीं रखेंगे। क्योंकि बाहर जाना, काम के लिए, कमाने के लिए जाना, पैसा.... If they want to go there to earn their livelihood, we cannot stop them and we should not stop them. Probably, conditions available in India are not as good as conditions outside in respect of earning. In respect of other matters, conditions may be different. We must understand that in various other countries, labour laws are not as good as they are in our country. But it is the choice of the people. They go there knowing very well that conditions as regards labour laws are not as good as they are in our country. They go their by their choice. If any difficulty arises, if anyone lands himself into any trobble, our missions abroad rush to his rescue. Even if he is a single person, an individual, our missions try to help him. Our missions there are carrying out this job....*(Interruptions)*....

SHRI RAM JETHMALANI: Mr. Chairman, Sir, I want to pay a compliment to this Government before I put my question. This Government of disparate elements has come into existence on the binding glue of secularism. I hope the hon. Minister realises that the area that is being talked about is an area in which secularism is conspicously absent. We are dealing with an area in which forms of worship with which we are familiar are not tolerated. Temples are not allowed to be constructed. Gurudwaras are not allowed to be constructed. The question which I want to put is this. Do our diplomatic agents in those countries proudly talk of the secularism with which they are bursting at home? Do they gently preach the virtues of secularism to their host Governments? *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: With all respect to the hon. member, I would like to submit that this is outside the ambit of this question.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, मेरे सवालात् का जवाब मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं स्पेसिफिकली यह जानना चाहता हूं कि जो लोग वहां जेल में हैं, उनको बाई एंड लार्ज कितना अरसा हुआ है, उनके ट्रायकल की प्रोग्रेस क्या है और सबसे बड़ी बात कि किस-किस जुर्म में लोग पकड़े गए हैं? यह सवाल, मैं इरादतन् इसकी ज्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अंदाज़ा मेरा यह है कि फर्ज़ कर लीजिए कि किसी का कार एक्सीडेंट होता है ऐवरीटाइम उसमें एक हिन्दुस्तानी और दूसरा गैर हिन्दुस्तानी है या वहीं का है, चाहे कुछ हो, गलती हिन्दुस्तानी की होती है तो मैं इस चीज़ को ज़हन में रखकर यह पूछ रहा हूं कि कब से लोग जेल में हैं, ट्रायल की प्रोग्रेस क्या है और किन-किन जुर्मों में वे जेल में हैं, यह बताइए?

†[شری سکندر بخت: صدر صاحب۔ میرے سوالات کا جواب مشکل ہو سکتا ہے لیکن میں "اسپیسیفیکلی" یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں جیل میں ہیں اللہ "بائی اینڈ لارج" کتنا عرصہ ہوا ہے۔ اسکے "ٹرائل" کی پروگریس کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کس جرم میں لوگ پکڑے گئے ہیں۔ یہ سوال میں "ارادتہ" اسکی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اسلئے پوچھ رہا ہوں۔ کیونکہ اندازہ میرا یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے "ایوریٹائم" اسمیں ایک ہندوستانی اور دوسرا غیر ہندوستانی ہے یا وہیں کا ہے۔ چاہے کچھ ہو۔ غلطی ہندوستانی کی ہوتی ہے تو میں اس چیز کو ذہن میں رکھکر یہ پوچھ رہا ہوں کہ کب سے لوگ جیل میں ہیں ٹرائل کی پروگریس کیا ہے اور کس کس جرموں میں وہ لوگ جیل میں ہیں۔ یہ بتلایئے۔]

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: The detailed break up is not readily available....(*Interruptions*)....

आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यह था कि:-

"whether some Indian citizens are leading a very miserable life in various Gulf countries. It is a general question.

SHRI SIKANDER BAKHT: I am not putting a general question. Please obtain the information and provide it.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में 198 ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may ask the External Affairs Minister for this information and provide it.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: We will obtain the information.

SHRI SIKANDER BAKHT: You should also provide it to us.

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Yes, Sir.

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद: सभापति महोदय, जिन एजेंसियों के माध्यम से हमारे युवाओं और महिलाओं को वेतन-वृद्धि की आशा दिलाकर वहां भेजा जाता है, क्या उन एजेंसियों पर हमारी सरकार का कोई नियंत्रण है और उन एजेंसियों के जो क्रियाकलाप हैं, उनका कोई रिकार्ड हमारे पास है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री रमाकांत डी. खलप: माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने दे रखा है।

This supplementary pertains to the Labour Ministry. There are certain laws and regulations under which these organisations are registered....(*Interruptions*)....

श्री जनार्दन यादव: आप लेबर मिनिस्ट्री से कन्सल्ट करके आते न।

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: A separate question may be asked.

Budgetary Allocation for National Waterways in Kerala

*203. SHRI THENNALA BALAKRISHNA PILLAI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total budgetary allocation for the work of National Waterways in Kerala during the last financial year;

(b) whether the allocated funds were fully utilised;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether the remaining funds are transferred to any other States?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) A provision of Rs. 1.00 crore was allocated in the Annual Plan 1995-96 (Central Scheme) for development of National Waterways in Kerala.

(b) and (c) The actual expenditure incurred during the year was Rs. 97.00 lakhs which is 97% of the total funds allocated.

(d) No, Sir.

SHRI THENNALA BALAKRISHNA PILLAI: Sir, the length of the national waterways in Kerala is so vast. So, when we consider such a vast length of waterways, the money allocated, that is, Rs. 1 crore, is meagre So, I would like to know from the hon. Ministe whether the Government has got a plan to increase the allocation to Kerala.

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, my earphone is not working. So, I couldn't hear the question.

MR. CHAIRMAN: The question is, since the waterway is very extensive in Kerala, the Member would like to know whether more funds will be allotted for the development of waterways.

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, I require notice for this question since it does not relate to the main question.....(*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: It does pertain to the main question. He has only asked about the allocation.